



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ४५]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर ४, १९७२ (कार्तिक १३, १८९४)

No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 4, 1972 (KARTIKA 13, 1894)

इस भाग में जिस पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस (NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र १५ फरवरी १९७२ तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 15th February 1972 :—

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
1	2	3	4

शून्य
—NIL—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी।
मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिए।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these *Gazettes*.

विषय-सची		पृष्ठ	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर)			
भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1121	भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर)	
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर)		भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—
भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1795	भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	—
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	135	भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोकसेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1541
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1577	भाग III—खंड 2—एकसूच कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	321
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—	भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	109
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—	भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1713
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर)		भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	217
भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं।)	—	पूरक संख्या 45—	
		28 अक्टूबर, 1972 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्टें	2165
		7 अक्टूबर, 1972 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े	2173

CONTENTS

PAGE	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1121
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1795
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	135
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1577
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (1)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (II)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	—
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	—
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1541
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	321
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	109
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1713
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	217
SUPPLEMENT NO. 45	
Weekly Epidemiological Reports for week-ending 28th October, 1972	2165
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 7th October, 1972.	211

भाग I—खण्ड 1

(PART I—SECTION 1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मंत्रिमंडल सचिवालय

(सांख्यिकी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 अक्टूबर 1972

सं० एम०-13013/4/71-रा० न० सर्वे०—इस विभाग के तारीख 28 जुलाई 1972 की अधिसूचना सं० एम० 13013/4/71-रा० न० सर्वे० 1 के पैरा 2 में आंशिक संशोधन के साथ, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता के अनुसंधान और प्रशिक्षण अध्ययन विद्यालय के संकायाध्यक्ष (डीन) डा० टी० बी० हनुराव, डा० टी० पी० चौधरी के स्थान पर सरकारी आंकड़े एवं रीति-विधान में प्रशिक्षण विषयक सलाहकार समिति के सदस्य होंगे।

दिनांक अक्टूबर 1972

गृह-पत्र

सं० बी० 11015/1/70-रा० न० सर्वे० II—भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के उमयनिष्ठ सेवा के पात्र कर्मचारियों को खपाने के उद्देश्य से इस विभाग की अधिसूचना संख्या बी-11015/1/70-रा० न० सर्वे० II दिनांक 18 मार्च 1972 के साथ राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन में तीन स्थानीय प्रशासनिक एककों का गठन किया गया जिनके कार्यालय कलकत्ता, नई दिल्ली तथा गिरिडीह (बिहार) में हैं। इन एककों के कर्मचारियों को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ा विभाजन प्रभाग तथा सर्वेक्षण, डिजाइन एवं अनुसंधान प्रभाग के अंग के रूप में आवंटित किया गया है और इस प्रकार उक्त अधिसूचना का परिच्छेद एतद्वारा निरसित किया जाता है।

ह० ल० कोहली, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 सितम्बर 1972

संकल्प

सं० फा० 10(4)/69-वक्फ—भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग संकल्प सं० फा० 10(4)/69-वक्फ दिनांक 9 दिसम्बर, 1970 जो भारत के राजपत्र के भाग I खण्ड 1 में 23 जनवरी, 1971 को प्रकाशित किया गया था, के द्वारा स्थापित वक्फ जांच समिति की अवधि को, जिसे संकल्प सं० फा० 10(4)/69-वक्फ, दिनांक 5 जून, 1972 के द्वारा 31 अक्टूबर, 1972 तक बढ़ा दिया गया था, एतद्वारा 30 अप्रैल, 1973 तक और बढ़ाया जाता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को, राज्य सरकारों, संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासकों आदि को भेज दी जाए।

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में सर्व-साधारण की सूचनार्थ प्रकाशित कर दिया जाए।

ई० वैकटेश्वरन, उप-सचिव

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 अक्टूबर 1972

सं० 41/38/71-न्यायिक (ख)—भारतीय विधि रिपोर्टों (दिल्ली अंकमाला) के प्रकाशन के बारे में, दिल्ली के प्रशासक के परामर्श से भारत सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है:—

- (i) ये नियम दिल्ली उच्च न्यायालय (विधि प्रतिवेदन परिषद्) नियम, 1971 कहे जायेंगे।
- (ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- ये भारतीय विधि रिपोर्टें (दिल्ली अंकमाला) जिन में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा किये गए निर्णय रद्द करेंगे एक परिषद् की देखरेख में प्रकाशित किये जायेंगे, जो कि दिल्ली उच्च न्यायालय की विधी प्रतिवेदन परिषद् कही जायेगी ('इसके पश्चात् इसे "परिषद्" कहा जायेगा)
- इस परिषद् का गठन निम्न प्रकार से किया जायेगा:—
 - दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीपति या उनके द्वारा प्रतिनिधित्व कोई न्यायाधीश (अध्यक्ष)।
 - मुख्य न्यायाधीपति द्वारा नामांकित किये गये दिल्ली उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश।
 - उच्च न्यायालय से सम्बद्ध केन्द्रीय सरकार का वरिष्ठ परामर्शदाता।
 - मुख्य न्यायाधीपति द्वारा नामांकित किये गये दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं की संस्था के दो सदस्य। उच्च न्यायालय के पंजीकार या इसके उप-पंजीकारों में से वह जिसे मुख्य न्यायाधीपति नामांकित करें, परिषद् के सचिव होंगे।

4. (i) भारतीय विधि रिपोर्टों (विल्सी अंकमाला) के संपादकीय कर्मचारी वर्ग में से एक संपादक, तथा उतने संवाददाता जितने दिल्ली का प्रशासक परिषद् के अध्यक्ष की सिफारिश पर निर्धारित करे, शामिल होंगे।
- (ii) संपादक के कार्यालय में उतने लिपिक कर्मचारी रखे जायेंगे जितने प्रशासक को समय-समय पर आवश्यक जान पड़ेंगे। यह उच्च न्यायालय स्थापना का अंग बन जायेगा तथा उन्हीं नियमों व शर्तों द्वारा प्रशासित होगा जो उच्च न्यायालय के कर्मचारी वर्ग पर लागू हैं।
5. (i) संपादक संवाददाताओं पर नियंत्रण रखेगा तथा उनकी झूटियाँ निश्चित करेगा और परिषद् की देखरेख में कार्य करेगा।
- (ii) संपादक तथा संवाददाताओं को देय वेतन की वरें परिषद् की सिफारिश पर दिल्ली के प्रशासक द्वारा निर्धारित की जायेंगी।
6. संपादकीय कर्मचारी वर्ग के सदस्य अस्थायी गैर-पैशन वाल पदों पर काम कर रहे अंश कालिक कर्मचारी होंगे। उनकी नियुक्तियाँ दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा उतने समय तक के लिए की जायेंगी जितना कि वह निर्धारित करें तथा इस प्रकार की नियुक्ति की अवधि समय-समय पर उनके द्वारा इस शर्त पर बढ़ाई जाएगी कि किसी कर्मचारी की सेवाएं किसी भी समय बिना कोई कारण बताये एक महीने का लिखित नोटिस देकर समाप्त की जा सकती हैं।
7. संपादकीय कर्मचारी वर्ग का कोई भी सदस्य किसी प्रलेख या सूचना को जो या तो उसके पास आई हो या उसके द्वारा झूटी के दौरान तैयार या एकत्रित की गई हो, रिपोर्टों से संबंधित अपनी झूटी के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिए चाहे वे कुछ भी क्यों न हो, प्रयोग में नहीं लायेगा।
8. रिपोर्टें दिल्ली प्रशासक के प्राधिकरण के अधीन प्रकाशित की जायेंगी तथा परिषद् को ऐसे प्राधिकरण के अधीन उन्हें प्रकाशित करने के लिए एतद् द्वारा अधिकार दिया जाता है।
9. रिपोर्टों के मुद्रण तथा वितरण से संबंधित सभी प्रबंधों के लिए दिल्ली का प्रशासक उत्तरदायी होगा।
10. मुख्य न्यायाधिपति की अनुमति से परिषद् अपने कार्य नियम स्वयं बना सकती है।
11. मुख्य न्यायाधिपति के अनुमोदन से परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले अनुदेशों के साथ साथ निम्नलिखित सामान्य नियमों तथा सिद्धांतों की रिपोर्टें

बनाते समय ध्यान में रखा जायेगा :—

- (क) प्रत्येक रिपोर्ट के साथ निर्णय को ठीक से समझने के लिए आवश्यक सभी तथ्यों का विवरण अवश्य होना चाहिए।
- (ख) रिपोर्ट में ऐसे कोई तथ्य न बतायें जायें जो निर्णय को समझने के लिए स्पष्ट रूप से अनावश्यक हों।
- (ग) किसी कथन को रखा जाए या छोड़ा जाए यह निर्णय करते समय कम विवरण देने के बजाय अधिक विवरण देने की गलती करना अधिक अच्छा होगा।
- (घ) यदि निर्णय में तथ्यों का स्पष्ट, पूर्ण तथा लगातार विवरण मौजूद है तो संवाददाता को शीर्ष टिप्पण में उनके विवरण देने की आवश्यकता नहीं है।
- (ङ) सामान्य नियम के रूप में, जिन मामलों के बारे में पूर्ण तथ्य प्राप्त नहीं किये जा सकते हैं, उनकी रिपोर्टें नहीं देनी चाहिए।
- (च) प्रत्येक रिपोर्ट में अधिवक्ता की बहुसंख्यकों का एक ऐसा विवरण अवश्य निहित होना चाहिए जिस से पर्याप्त रूप में यह दिखाई दे कि न्यायालय में कितनी बातों पर बल दिया गया तथा साथ ही साथ बहुसंख्यकों के केवल संक्षिप्त तथा सूक्ष्म शीर्षक जाने दिये चाहिए।
- (छ) यदि किसी निर्णय या कोई विशेष प्रभाव किन्हीं अन्य निर्णयों अथवा विधि के किसी सिद्धांत पर पड़ता हो और वह रिपोर्ट के तथ्यों से स्वतः स्पष्ट न होता हो तो रिपोर्टर को उसकी ओर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट कराना चाहिए।
- (ज) हर रिपोर्ट में न्यायालय और उसके हर न्यायाधीश द्वारा किए गए निर्णय के विवरण की एक पूरी प्रति अथवा निर्णय का उतना भाग अवश्य रखना चाहिए जो उस मुद्दे से सम्बद्ध हो जिसके कारण उस मामले की रिपोर्ट दी जा रही है।
- (झ) सामान्यतः नियम यह होना चाहिए कि निम्न-लिखित मामलों की रिपोर्टें न की जायें : वे मामले जो मात्र साक्ष्य अथवा तथ्यों पर आधारित हैं, वे मामले जो निजी प्रलेखों की रचना से संबद्ध हैं और वे मामले जिनमें विधि के किसी विशेष सिद्धांत का उदाहरण प्रस्तुत नहीं होता अथवा जो किसी संविधि पर कुछ ऐसा विशेष प्रभाव नहीं डालते जैसा कि पिछले निर्णयों से न पड़ा हो। जहां किसी रिपोर्ट में विधि और तथ्य दोनों पर विचार हुआ हो वहां मात्र तथ्यों से सम्बद्ध अंश छोड़ दिया जाय।

(अ) रिपोर्टरों के लिए मुकद्दमों का चयन करते समय रिपोर्टर को निर्णय के भार तथा महत्व और संतोष-जनक रिपोर्ट के लिए सामग्रियों की विद्यमानता से प्रेरित होना चाहिए और उसे किसी मुकद्दमे को रिपोर्ट करने से केवल इस लिए नहीं छोड़ देना चाहिए कि वह निर्णय को गलत मानता है या कि उसे अन्य निर्णयों का विरोधी मानता है।

(त) जब तक वह न्यायाधीश या वे न्यायाधीश जिन्होंने निर्णय दिया है यह न चाहें कि उसकी रिपोर्ट दी जाय तब तक किसी निर्णय की रिपोर्ट नहीं दी जानी चाहिए परन्तु यदि परिषद् चाहे तो स्वयं अपनी या संपादक द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय कर सकती है कि उस निर्णय को रिपोर्ट नहीं किया जायेगा।

(थ) जब कभी कोई निर्णय या मुकद्दमा किसी स्थानीय या विशेष संविधि की किसी धारा या किसी विशेष उप-नियम या सांविधिक नियम के निर्वचन पर आधारित हो तो संपादक को विवरण के तथ्यों की पद्धतिपूर्ण के रूप में उक्त धारा, उपनियम या नियम को उद्धृत करना चाहिए।

कै० त्यागराजन, उपसचिव

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 अक्टूबर 1972

सं० 7(5)/71-को०II—भारत सरकार द्वारा प्रबन्ध निदेशक, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को, कोयला सलाहकारी परिषद् के सदस्य के रूप में नाम निर्देशित करने का विनिश्चय किया गया है। खान विभाग के संकल्प संख्या को० II 7(5)/71, तारीख 20 जुलाई, 1971 द्वारा पुनर्गठित कोयला सलाहकारी परिषद् की संरचना में तदनुसार निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा :—

उपरोक्त संकल्प के पैरा 2 में “सदस्य” शीर्षक के अधीन निम्नलिखित जोड़ा जाय :—

प्रबन्ध निदेशक भारत कोकिंग कोल लिमिटेड।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मन्त्रिमंडल सचिवालय, संसदीय मामलों के विभाग, योजना आयोग, राष्ट्रपति के निजी और सैनिक सचिव, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और महालेखाकार वाणिज्य, निर्माण और विविध सहित समस्त सम्पत्तियों को संसूचित की जाय।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

शरण बिहारी लाल, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक अक्टूबर 1972

सं० 8(1)/72-को०II—भारत सरकार ने खान हजी-नियंत्रण शिक्षा और प्रशिक्षण के बारे में संयुक्त बोर्ड में, जो पिछली बार खान विभाग की अधिसूचना संख्या 8(1)/72-को०II तारीख 11 फरवरी, 1972 द्वारा पुनर्गठित किया गया था, तकनीकी शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिषद् के प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में नाम निर्देशित करने का विनिश्चय किया है। संयुक्त बोर्ड की विद्यमान संरचना को तदनुसार निम्नलिखित रूप से संशोधित किया।

अपरवर्णित अधिसूचना के पैरा 2 में, “सदस्य” के आधीन

“तकनीकी शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिषद् का प्रतिनिधि” जोड़ा जाए।

निरंकार स्वरूप मदनगिर, उप-सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 अक्टूबर 1972

संकल्प

सं० 30-1/71-पशुधन विकास-III—इस मंत्रालय के संकल्प संख्या 30-1/71-पशुधन विकास-III, दिनांक 12-4-72 के क्रम में तथा इस मंत्रालय के संकल्प सं० 20-20/69-पशुधन विकास-II, दिनांक 26/29-11-69 में आंशिक संशोधन करते हुए, भारत सरकार ने निर्णय किया है कि प्रशासन निदेशक, विस्तार निदेशालय द्वारा केन्द्रीय गोसंवर्द्धन परिषद् के करण्ट एकाउण्ट के संचालन की तिथि पहली अक्टूबर, 1972 से 31 मार्च 1973 तक अथवा जब तक अनिर्णीत दावों का निर्णय किया जाता है, जो कोई भी पहले हो, आगे बढ़ाई जाती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सब राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा भारत सरकार के सब मंत्रालयों और विभागों, योजना आयोग मन्त्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, तथा राज्य सभा सचिवालय को भेजी जायें।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

बी० पी० गुलाटी, उप-सचिव

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 अक्टूबर 1972

सं० एफ० 7-3/72-स्कूल-1—राव बहादुर बन्धु जी जनार्दन चौवल पुरस्कार निधि के सम्बन्ध में जबकि, कार्यालय आपन सं० एफ० 7-3/72-स्कूल-I दिनांक 21-10-72 के जरिए भारतीय पूर्त अक्षयनिधि के कोषाध्यक्ष की राव बहादुर बन्धु जी जनार्दन चौवल पुरस्कार निधि से सम्बन्धित 1,000/- रु० के चार प्रतिशत मध्य प्रदेश ऋण, 1971 के निष्क्रमण

लाभ को 5३ प्रतिशत मध्य प्रदेश ऋण, 1983 में पुनः निवेश करने से संबन्धित शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय की कार्योत्तर स्वीकृति अभिप्रेषित की गयी थी।

और जबकि, भारतीय पूर्त अक्षयनिधि के कोषाध्यक्ष की हैसियत से पूर्वअक्षयनिधि के मध्य प्रदेश के कोषाध्यक्ष ने यह सूचित किया है कि चूंकि उक्त पुनः निवेशन 921.02 रुपये की लागत से 900/- रुपये के अंकित मूल्य में 5३ प्रतिशत मध्य प्रदेश ऋण, 1983 में लगाकर पूरा हो गया है, और अब इस प्रकार से केवल 78.98 रु० (इस राशि के व्यौरे संलग्न विवरण में दिये हुए हैं) का बकाया बिना निवेश के रह गया है, जो कि निवेशन के लिए बहुत कम रकम है और इस लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों को वापिस की जानी है।

अब इसलिए, पूर्त अक्षयनिधि अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारतीय पूर्त अक्षयनिधि के कोषाध्यक्ष को निवेशन न की गयी 78.02 (अटुत्तर रुपये दो पैसे केवल) की रकम को राव बहादुर बन्धुजी जनार्दन चौबल पुरस्कार निधि के प्रशासन में कार्य कर रहे व्यक्ति को वापिस करने का आदेश देती है।

ए० एन० धवन, सहायक शिक्षा सलाहकार

CABINET SECRETARIAT

(Department of Statistics)

New Delhi, the 11th October 1972

No. M-13013/4/71-NSS.I.—In partial modification of para 2 of this Department Notification No. M.13013/4/71-NSS.I, dated the 28th July, 1972, Dr. T. V. Hanurav, Dean of Studies of the Research and Training School of the I.S.I., Calcutta, will be a member of the Advisory Committee on Training in Official Statistics and Related Methodology vice Dr. T. P. Chaudhuri.

The 19th October 1972

No. V-11015/1/70-NSS.II.—With para 3 of this Department's Notification No. V-11015/1/70-NSS.II, dated the 18th March, 1972, three Local Administrative Units were set up in the National Sample Survey Organisation, with their offices at Calcutta, New Delhi and Giridih (Bihar) for absorption of eligible common services staff of the Indian Statistical Institute. The members of staff of these units have since been allocated to form part of the Data Processing Division and Survey, Design & Research Division of National Sample Survey Organisation, and para 3 of the said Notification is as such hereby cancelled.

H. L. KOHLI, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

RESOLUTION

New Delhi, the 27th September 1972

No. F.10(4)/69-Wakf.—The term of the Wakf Inquiry Committee set up by the Government of India, Ministry of Law & Justice, Legislative Department, Resolution No. F.10(4)/69-Wakf, dated the 9th December, 1970, published in the Gazette of India, Part I, Section 1, dated the 23rd January, 1971, and extended up to 31st October, 1972, vide Resolution No. F.10(4)/69-Wakf, dated the 5th June, 1972, is hereby further extended up to the 30th April, 1973.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the Ministries/Departments of the Government of India, State Governments, Administrators of Union Territories, etc.

सिचाई और विद्युत् मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्टूबर 1972

संकल्प

सं० वि०का० दो-34(2)/71—1 मई, 1972 से श्री एस० गोपालन, मुख्य अभियन्ता (सार्वजनिक निर्माण विभाग) बृहत् सिचाई तथा सामान्य, आंध्र प्रदेश, श्री वी० सूर्यनारायण, मुख्य अभियन्ता (परियोजना) आंध्र प्रदेश के स्थान पर सिचाई और बहुदेशीय परियोजनाओं के लागत-प्राक्कलनों में बड़ी संख्या में बार-बार ऊर्ध्वोन्मुखी संशोधनों के कारणों की वैज्ञानिक जांच-पड़ताल करने के लिए इस मंत्रालय के संकल्प सं० वि०का० दो-34(2)/71 दिनांक 25 जनवरी, 1972 द्वारा गठित समिति के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र के खण्ड एक, भाग एक में प्रकाशित कर दिया जाए।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों और समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को भेज दी जाए।

सत्येन्द्र नाथ गुप्ता, संयुक्त सचिव

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

E. VENKATESWARAN, Dy. Secy.

(Department of Justice)

New Delhi, the 12th October 1972

No. 41/38/71-Judl.(B).—The following rules are hereby made by the Government of India, in consultation with the Administrator of Delhi, with regard to the publication of the Indian Law Reports (Delhi Series) :—

1. (i) These rules shall be called the Delhi High Court (Council of Law Reporting) Rules, 1971.
- (ii) They shall come into force from the date they are published in the official Gazette.
2. The Indian Law Reports (Delhi Series) containing the decisions of the High Court of Delhi shall be published under the supervision of a Council to be called "the Law Reporting Council of the High Court of Delhi" (hereinafter called "The Council").
3. The Council shall be constituted as follows :—
 - (i) The Chief Justice of the High Court of Delhi or a Judge deputed by him (Chairman).
 - (ii) Two Judges of the High Court of Delhi to be nominated by the Chief Justice.
 - (iii) The senior counsel of the Union Government attached to the High Court.
 - (iv) Two members of the Delhi High Court Bar Association to be nominated by the Chief Justice.

The Registrar of the High Court or such one of its Deputy Registrars as the Chief Justice may nominate shall be the Secretary of the Council.

4. (i) The editorial staff of the Indian Law Reports (Delhi Series), shall consist of the Editor, and such number of Reporters as the Administrator of Delhi may prescribe on the recommendation of the Chairman of the Council.

- (ii) The office of the Editor shall have so much of clerical staff as may be found necessary from time to time by the Administrator. It shall form part of the High Court Establishment and be governed by the same rules and conditions as are applicable to the members of the High Court staff.
5. (i) The Editor shall have control over and define the duties of the Reporters and shall work under the supervision of the Council.
- (ii) The rates of remuneration payable to the Editor and the Reporters shall be fixed by the Administrator of Delhi on the recommendation of the Council.
6. Members of the editorial staff shall be part time servants holding temporary non-pensionable posts. They shall be appointed by the Chief Justice of the High Court of Delhi for such period as he may determine and the period of such appointment may from time to time be extended by him, provided that the services of any member may be terminated at any time on one month's notice in writing without assigning any reason.
7. No member of the editorial staff shall use for any purpose whatsoever other than his duties in connection with the Reports any document or information which has either come into his possession or has been prepared or collected by him in the course of such duties.
8. The Reports shall be published under the authority of the Administrator of Delhi and the Council is hereby empowered to publish them under such authority.
9. The Administrator of Delhi shall be responsible for all the arrangements connected with the printing and distribution of the Reports.
10. The Council may with the approval of the Chief Justice, make its own rules of business.
11. Subject to such instructions as may from time to time with the approval of the Chief Justice be issued by the Council, regard shall be had in framing the Reports to the following general rules and principles:—
- Every report ought to contain a statement of all facts necessary for a due understanding of the decision.
 - A report may not state any facts which are clearly unnecessary for a due understanding of the decision.
 - In judging whether to insert or to omit a statement of facts, it is better to err on the side of over statement than of under statement.
 - The reporter need not state the facts in the head note if there is a clear, full and consecutive statement of them in the judgement.
 - As a general rule, cases for which a full statement of facts cannot be obtained are not to be reported.
 - Every report ought to contain such a statement of the arguments of the counsel as should be sufficient to show what points were pressed before the court and at the same time brief and precise, merely the heads of the arguments being given.
 - The Reporter should note any material bearing which the decision may have on other decisions or on any principle of law and which is not otherwise apparent on the fact of the report.
 - Every report ought to contain a full copy of account of the judgement delivered by the Court and by each Judge thereof, or of so much of the judgement as bears on the point for which the case is reported.
 - As a general rule, cases turning upon evidence or inferences of facts, cases relating to the construction of private documents and cases which do not illustrate some principle of law or do not have some important bearing on an enactment in a way not covered by previous decisions ought not to be reported. Where a report deals with issue of law as well as facts the portion concerned with facts alone may be omitted.

- (j) In selecting cases for the Reports, the Reporter is to be guided by the weight and importance of the decision and the existence of materials for a satisfactory report, and he should not abstain from reporting a case merely because he may think the decision to be erroneous or to be in conflict with the other decisions.
- (k) No judgement should be reported unless the Judge or the Judges who delivered the judgement desire that it should be reported but the Council may either on its own or on a report made by the Editor decide that it shall not be reported.
- (i) Whenever a judgement or a case turns upon the interpretation of a section of a local or special Statute, or upon certain bye-law or Statutory rule the pertinent section of bye-law or rule should be quoted by the Editor as a footnote to the statement of facts.

K. THYAGARAJAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF STEEL AND MINES
(Department of Mines)

RESOLUTION

New Delhi, the 18th October 1972

No. 7(5)/71-CII.—It has been decided by the Government of India to nominate the Managing Director, Bharat Coking Coal Limited as a Member of the Coal Advisory Council. The following amendment may accordingly be made in the composition of the Coal Advisory Council which was reconstituted *vide* the Department of Mines Resolution No. CII-7(5)/71, dated the 20th July, 1971:—

In para 2 of the aforesaid Resolution, under the heading "Members" please add the following:—

Managing Director, Bharat Coking Coal Limited.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all concerned including all the Ministries of the Government of India, the Prime Minister's Secretariat, the Cabinet Secretariat, the Department of Parliamentary Affairs, the Planning Commission, Private and Military Secretaries to the President, the Comptroller and Auditor General of India, the Accountant General, Central Revenues, and the Accountant General, Commerce, Works and Miscellaneous, New Delhi.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. B. LAL, Jt. Secy.

New Delhi, the 18th October 1972

No. 8(1)/72-CII.—The Government of India have decided to nominate a representative of the All India Council for Technical Education as a Member on the Joint Board on Mining Engineering Education & Training which was reconstituted last *vide* the Department of Mines Notification No. 8(1)/72-CU, dated the 11th February, 1972. The present composition of the Joint Board may accordingly be amended as follows:—

In para 2 of the above mentioned Notification, under "Members"

Please add "A representative of the All India Council for Technical Education".

N. S. BHATNAGAR, Dy. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture)

RESOLUTION

New Delhi, the 12th October 1972

No. 30-1/71-L.D.III.—In continuation of this Ministry's Resolution No. 30-1/71-L.D.III, dated the 12th April, 1972 and in partial modification of this Ministry's Resolution No. 20-20/69-L.D.III, dated 26/29-11-69, the Government of India have decided that the date upto which the Director of Administration, Directorate of Extension may operate on the current account of the Central Council of Gosamvardhana be further extended from 1-10-72 to 31-3-73 or till the pending claims are settled, whichever is earlier.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments, Administration of Union Territory, all the Ministries of the Government of India, the Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, the Lok Sabha Secretariat and the Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. P. GULATI, Dy. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE

(Department of Education)

New Delhi, the 21st October 1972

**IN THE MATTER OF RAO BAHADUR BANDHUJI
JANARDHAN CHAUBAL PRIZE FUND**

No. F.7-3/72-Schools-I.—WHEREAS by the Office Memorandum No. F.7-3/72-Schools-I, dated the 21st October, 1972, *ex-post facto* sanction of the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Education) was conveyed to the Treasurer of Charitable Endowments for India regarding re-investment of the redemption proceeds of the 4% M.P. Loan 1971 for Rs. 1,000/- relating to Rao Bahadur Bandhuji Janardhan Chaubal Prize Fund in 54% M.P. Loan 1983;

AND WHEREAS the Treasurer of Charitable Endowments, Madhya Pradesh, as agent of the Treasurer of Charitable Endowments for India has reported that the re-investment has since been completed by subscribing to the 54% M.P. Loan 1983 of the face value of Rs. 900/- at a total cost of Rs. 921-02, thus leaving an un-invested balance of Rs. 78.98 (details of transactions are given in the attached

Statement), which is to small as an amount for investment and has, therefore, to be refunded to the authorities concerned;

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890) the Central Government hereby directs the Treasurer of Charitable Endowments for India, to refund the said un-invested balance of Rs. 78.98 (Rupees Seventy eight and paise ninety eight only) to the person acting in the administration of the Rao Bahadur Bandhuji Janardhan Chaubal Prize Fund.

A. N. DHAWAN, Asstt. Educational Adviser

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER**RESOLUTION**

New Delhi, the 10th October 1972

No. DW.II-34(2)/71.—With effect from 1st May, 1972, Shri S. Gopalan, Chief Engineer (P.W.D.) Major Irrigation and General, Andhra Pradesh will act as Member in place of Shri V. Suryanarayana Chief Engineer (Projects), Andhra Pradesh on the Committee, set up under this Ministry's Resolution No. DW.II-34(2)/71, dated the 25th January, 1972, for making scientific investigation into the causes leading to the frequent large number of upward revisions in the cost estimates of irrigation and multi-purpose projects.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India, Part I, Section 1.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of India, all the State Governments/ Administrations of Union Territories and the Chairman and Members of the Committee.

S. N. GUPTA, Jt. Secy.